1998-99, ten pillion shares held by the Government in Videsh Sanchar Nigam Limited were sold as GDRs and an amount of about Rs. 785 crores has been realised.

Investment of Provident Fund in Equities of Private Companies

77. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal
under consideration to invest part of provident
fund of employees in equities of private companies; if so, the details thereof; and

(b) whether trade unions have been consulted in this regard; if so, what is their opinion in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) and (b) The pattern of investment to be followed by the non-Government provident funds has a provision enabling the Trusts, subject to their assessment of risk-return prospects, to invest upto 10% of the incremental accretions in' private sector bonds/securities, which have an investment grade rating from at least two credit rating agencies. It is at die sole discretion of the Board of Trustees and there is no compulsion whatsoever.

एस्सार समूह पर बकाया ऋण एवं अग्रिम राशि

78. **श्री दिदलीप सिंह जूदेव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)"एस्सार" समूह पर आज की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों एवं अग्रिम राशियों कका ब्यौरा क्या हैं;

(ख)इस राशि पर कितने प्रतिशतत ब्याज वसूल किया जा रहा है;

(ग)"एस्सार" समूह द्वारा अन्य देशों के साथ किये जा रहे कारोबार का अद्यतन ब्यौरा क्या हैं; और

(घ)क्या सरकार द्वारा समय-समय पर इस कारोबार की समीक्षा की जा रही हैं?

वित्त मंत्रालय बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम0 आर0 जर्नादनन) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा एस्सार ग्रुप को दिए गये ऋणों एवं अग्रिम राशि को बकाया राशि निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रूपये)

संस्थाएं	राशि
आई डी बी आई	164.73 (दिनांक 1.2.1999 की स्थिति के अनुसार
आई एफसी आई	1169.58 (दिनांक 0.2.1999 ककी स्थिति के अनुसार)
आई सी आई सी आई	836.26 (दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार)

वित्तीय संस्थाओं द्वारा रूपया ऋणों पर ब्बयाज 16 प्रतिशत और 20 प्रतिशत (ब्याज दर को छोड़कर) के बीच प्रभावित की जाती है और विदेशी मुद्रा ऋण पर यह -105 प्रतिशत लाइबौर तथा +3.7 प्रतिशत लाइबौर होती है

(ख)और (घ) जानकारी के एकत्र की जा रही हैं और यथा उपलब्ध जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वित्तीय घाटे का मुकाबला करने के लिए राजसहायता में कटौती

79. **श्री राज मोहिन्दर सिंह** :
श्री कपिल सिब्बल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच है कि सरकार ने चालू वर्ष के दौरान बजटीय घाटे को कम करने के लिए देश में विभिन्न मदों पर दी जाने वाली राजसहायता की राशि में कटौती की हैं;

(ख)यदि हां, तो किस-किस मद पर दी जाने वाली राजसहायता की राशि में कटौती की गई; और

(ग)वे मदें कौन-कौन सी हैं जिन पर राजसहायता की राशि में चालू वर्ष के दौरान कटौती नहीं की गई तथा सरकार द्वारा बजटीय घाटे को कम करने के लिए राजसहायता की राशि में कटौती हेतु मदों के चयन के लिए क्या नियम किए गए थे?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) वर्ष 1998-99 के लिए केन्द्रीय सरकार में 22025 करोड़ रूपये की कुल सब्सिडी की बजटीय व्यवस्था की गई थी। केन्द्रीय सरकार का यह प्रयास रहा है कि सब्सिडी प्रणाली को सुस्पष्ट बनाकर तथा जहां आवश्यकता हो सब्सिडी प्राप्त मदों के मूल्यों में परिवर्तन करके सब्सिडी प्रणाली को तर्कसंगत बनाया जाए। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की आवश्यकताओं और समाज के संवेदनशील वर्गो के हितों की सुरक्षा की जरूरत को संतुलित करते हुए सरकार ने "गरीबी की रेखा से ऊपर की " श्रेणी से संबंधित लाभानुभोगियों के लिए गेहूं और चावल पर सिब्सिडी की वृद्धि पर रोक लगा का प्रयास किया जा रहा है। चीनी और यूरिया पर भी सब्सिडी की वृद्धि पर रोक लगाई गई हैं। चीनी सब्सिडी पर नियंत्रण का उद्देश्य सब्सिडी का बेहतर लक्ष्य निर्धारित करना है जबकि यूरिया सब्सिडी में वृद्धि पर रोक का उद्देश्य भिन्न-भिन्न किस्मों के उर्वरकों के और अधिक संतुलित उपयोग को बढ़ावा उपयोग देना है।

Raw Silk Import Racket

80. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "DRI bursts massive raw silk import racket"; if so, the details/status of investigations carried by DRL on extensive custom duty evasion scam;

(b) the details of bank guarantees encashed so far in the scam and the details of banks involved therein; and

(c). the action taken against the arring banking officials?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) The Government is aware of the news item which refer to a case of abuse of Duty Exemption Scheme taken up for investigation by DRI in later half of 1998. In this case investigations conducted by DRI so far have revealed that on the strength of advance licences procured on forged/bogus documents, duty free imports of raw silk were made through 25 companies of an organised syndicate. A number of these firms have been found fictitious/non-existent at given addresses. In addition to forgery in documentation, it was found that though the said advance licences were issued by officers of DGFT with the status of "Merchant Exporter", at the time of submission of these licences before custom authorities, the status of the licences was interpolated to read as "manufacturer exporter". This tempering has been done to reduce the liability of the importer to execute bank guarantee which is required @ 25% of duty liability in the case of "manufacturer exporter" *vis-a-vis* 100% bank guarantee requirement in the case of "merchant exporter". In some cases, bank guarantees produced before customs authorities have also been found to be *prima facie* forged ones. During investigations, 2 consignments of tussar silk/silk fabric valued at Rs. 60 lakhs were seized at Calcutta docks. No one has come forward to claim these goods so far. The DRI has arrested 5 persons in this case in January, 1999. Exact quantification of duty evasion shall be possible only on completion of the ongoing investigations.

(b) So far, 13 (thirteen) bank guarantees for an amount of Rs. 67 lakhs have been encashed. These bank guarantees were of Bank of Maharashtra. As regards forged Bank guarantees, these were of Bank of Punjab, New Delhi and Bank of Madura, New Delhi.

(c) Statement of two bank officials have been recorded. Action against bank officials would depend on the result of investigations.

Suggestion of ASSOCHAM for moratorium on revenue expenditure

81. SHRI RAGHAVJI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Associated Chambers of Commerce and Industry has suggested a five year moratorium on revenue expenditure and